229

संख्या864/XVIII(II)/2013–18(58)/2011

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गढवाल ।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 15 मई, 2013

विषयः–जनपद गढवाल के स्थान सुमाड़ी में एन0आई0टी0 की स्थापना हेतु 4.261 है0 अतिरिक्त भूमि, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र सं0–31 कैम्प/8 ए0एल0सी0(2011–12) दिनांक–05.03.2013 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या–35/XVIII(II)/2013–18(58)/2011 दिनांक 18 जनवरी, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद गढवाल के सुमाडी में नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एन0आई0टी0) की स्थापना हेतु ग्राम चमराडा पट्टी कटूलस्यूँ तहसील श्रीनगर में आपके द्वारा संस्तुत/अनुमोदित विभिन्न खसरा संख्याओं में अंकित कुल 4.261 है0 अतिरिक्त भूमि, वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15–2–2002 में निहित प्राविधानों एवं प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नही की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

8– प्रश्नगत भूमि आंवटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9. इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो के बिन्दु संख्या–1–9 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी,जिसके लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0संख्या-864/समदिनांकित/2013

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
4– उप निदेशक, नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, श्रीनगर, गढवाल।
5– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय देहरादून।
6– प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।